LP-DPC/4.00/2L

श्री मेघराज जैन (क्रमागत) : हमारे जिन वैज्ञानिकों ने शोध किया है, उन्होंने यह बात कही है कि माँ के दूध में भी ज़हर आ गया है। इसीलिए यदि इस रासायनिक खाद का बहिष्कार करके जैविक खाद से अनाज पैदा किया जाए, तो लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा।

उपसभापति जी, मैंने ऐसी जानकारी अखबारों में पढ़ी है, पत्रिकाओं में यह पढ़ा है कि आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में और पास के ही दो जिलों में रासायनिक खाद का एक दाना नहीं आता है। गाय के गोबर से गैस बनाई जा सकती है, गाय के गोबर से खाद बनाई जा सकती है, गाय के गोबर से अमृत पानी बनाकर, अगर तत्काल खेत को सींचा जाए, तो उससे एक एकड़ जमीन बहुत अच्छी हो सकती है। इस प्रकार बूढ़ी गाय, जो दूध नहीं देती है, वह भी हमारे लिए उपयोगी है। मुझे पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर करीब-करीब सत्तर गौशालाएँ ऐसी हैं, जिनके अंदर गौमूत्र से औषधियाँ बनती हैं और लोगों पर उन दवाइयों से अनेक रोगों का इलाज भी करते हैं। मैंने मध्य प्रदेश के अंदर, जब मैं गौ समर्थन बोर्ड का अध्यक्ष था, तीन दिन की एक कार्यशाला की थी। उसमें देश के 29 वैज्ञानिक आए थे। पहले दिन, गौ समर्थन कैसे करना है, दूसरे दिन, जैविक खेती कैसे करनी है, उससे क्या लाभ हैं और तीसरे दिन गौमूत्र से औषधियाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ किस प्रकार से बना सकते हैं, इनका कार्यक्रम रखा गया था।

भैषज्य रत्नावली में इस बात का उल्लेख है कि गौमूत्र के अनुपान से दी गई औषधि आयुर्वेदिक की तुलना में 10 से लेकर 40 प्रतिशत तक ज्यादा लाभ देती है। हमें इन सब पर अनुसंधान करना चाहिए। किसी बात का विरोध केवल आँख मींच कर करें, यह बात ठीक नहीं है। हमारे डेनियल राजा जी हैं, उन्होंने इस पर कहा है। ठीक है, यह उनका अपना विचार है, उनकी पार्टी का विचार है। वर्ग संघर्ष कैसे हो, किस प्रकार भारत की हर चीज को नकारा है, उनकी विचारधारा पर, उनकी इस बात पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने विरोध किया है, वे अपनी जगह पर ठीक हैं। उन्होंने उनकी विचारधारा के हिसाब से विरोध किया है, यह उनका अपना मत है, लेकिन मैं देश के हित के लिए कहना चाहता हूं, लोगों के स्वास्थ्य के हित के लिए कहना चाहता हूं कि मैंने इसके लिए गाँव में एक महीने तक बैल गाड़ी से यात्रा की और गाँव-गाँव में जाकर किसानों से बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं गाय बचाने के लिए कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं यह कहने आया हूं कि अगर मरने से बचना है तो गाय की शरण में जाओ, नहीं तो यह अनाज, जो हम खा रहे हैं, जो सब्जियाँ खा रहे हैं, इनसे देश में जिस प्रकार की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उस संदर्भ में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इस प्रकार की एक एजेंसी बनाए, जो यह जाँच करे कि वास्तव में क्या स्थिति है। मैं अभी करनाल गया था। ..(समय की घंटी)..हमारी संसदीय समिति की बैठक में..(समय की घंटी)..समिति के दौरे में..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. Your time is over now. …(Interruptions) …

श्री मेघराज जैन : एक सैकंड, मैं खत्म कर रहा हूं। उस कमेटी में वहाँ के वैज्ञानिकों बताया कि एक दूध है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ..(व्यवधान)..और वह हम केवल भारतीय नस्ल की गाय के द्वारा ही ..(व्यवधान).. प्राप्त कर सकते हैं। ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, hon. Minister …(Interruptions)…

श्री मेघराज जैन : उन्होंने अलग से दूध पेश ..(व्यवधान)..करना शुरू कर दिया है। ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister to reply. …(Interruptions) …

Please …(Interruptions)…

श्री मेघराज जैन : गाय का संरक्षण होना चाहिए।..(व्यवधान)..इसका धार्मिक ..(व्यवधान)..से कुछ लेना-देना नहीं है। ..(व्यवधान)..जावेद भाई ने जो बात कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ..(व्यवधान)..सारे समाज को एक साथ लेकर..(व्यवधान)..सबकी सहमति बनाकर एक कानून लाना चाहिए। ..(व्यवधान)..

(समाप्त)

श्रीमती छाया वर्मा : उपसभापति जी, मैं दो मिनट बोलना चाहती हूं।

श्री पी.एल. पुनिया : उपसभापति जी, ..(व्यवधान)..दो मिनट दे दीजिए। ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. …(Interruptions) … The Bill has to be over in two hours. Sorry, there is one more name. One minute, please. Time allotted to the Bill is two hours according to the Rule. So, I have to close everything by 4.30 p.m. …(Interruptions) … Navaneethakrishnan*ji*, I am giving you two minutes only. …(Interruptions) …

SHRIMATI CHHAYA VERMA: Sir, …(Interruptions) …

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot violate the rules. …(Interruptions) … Don't ask me to violate the rule. …(Interruptions) … He told me. It is his party's time and he came in advance and told me…(Interruptions) … But she gave the name later. …(Interruptions) …

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (TAMIL NADU): Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir. …(Interruptions) … Cow is a sacred animal. It is a domestic animal. I would like to highlight the benefits of cow. No controversial statement from me. …(Interruptions) … I know, in all

villages, each and every household will have a cow or more than one cow because the cow urine and cow milk are used for the family members.

(Contd. by KSK/2m)

KSK/KLG/4.05/2M

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (CONTD.): From health point of view, cow milk is very essential. Breast feeding is considered best for children, but sometimes, mothers are not able to feed, hence they resort to cow milk to be provided to their children. So, from health point of view also, cow milk is essential for us. Sir, nowadays, we see that no milk is available without adulteration. We have to create sensitization among our own people to protect the cows so that we can get pure and unadulterated milk. For organic farming, a liquid preparation called, panchagavya, is made. In Thanjavur area, one farmer is exporting and earning crores and crores of rupees by preparation of panchagavya. In the preparation of panchagavya, the cow urine is very essential. Also, for the preparation of thiruneer, vibhuthi, which is worn on the forehead of every human being,…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak about the Bill. Why are you wasting the time? You have to say either you support the Bill or you oppose it. Why are you saying all this?

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: The cow has to be protected at any cost.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is good. Now, the Minister.

श्रीमती छाया वर्मा: सर, दो मिनट। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill has to be disposed of within 30 minutes. The Minister will reply; then the Member has also to reply, and then voting. ...(Interruptions)... That is not the way. I cannot allow that. ...(Interruptions)... Anybody can come like this. Should I allow everybody? That is not the way. She could have given her name in advance. Pressurizing the Chair and trying to speak is not allowed. I cannot accept that. Now, the Minister.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): उपसभापति महोदय, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का आभारी हूँ, जो वे यह विषय यहां सदन में लाए हैं और जिसको लेकर पूरे देश में हमारे आठ माननीय सदस्यों के द्वारा यह मैसेज दिया गया कि हिंदुस्तान के जीवन के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य

डी. राजा साहब ने कहा कि गाय जानवर है। हम सब लोग जानते हैं कि गाय जानवर है और हम सब लोग मनुष्य हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हैं। मनुष्यों में विशिष्ट मनुष्य भी होते हैं, जिनका समय-समय पर हम सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी भी मनुष्य रहे हैं। गाय जानवर है, इसमें दो राय नहीं हैं, महात्मा गांधी मनुष्य थे, इसमें भी दो रायें नहीं हैं। गाय को इस समाज में कुछ कारणों से विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अब हिंदुस्तान के अंदर मज़हब के आधार पर गाय के लिए कोई जान दे, मज़हब के आधार पर कोई गाय के विरोध में हत्या करे, यह उनका विषय हो सकता है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हिंदुस्तान की अपनी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। राजा साहब मजदूरों के नेता हैं और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान के गरीब और सीमांत किसान का भी अपना महत्व है। यह बात सब को पता है कि ग्रामीण परिवार की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी रीढ़ पशुधन है और इसलिए पशुधन को राष्ट्रधन कहा गया है। यहां गाय का विशेष महत्व इस कारण से आता है कि जो लघु और सीमांत किसान हैं, जो 80 प्रतिशत दूध देने वाली गायें है, वे इन मजदूर परिवारों के पास हैं, किसान परिवारों के पास हैं। ये 80 प्रतिशत जो गायें हैं, इनकी स्थिति यह है कि देश में जो कुल दूध का उत्पादन होता है, उसका मात्र 20 प्रतिशत इन 80 प्रतिशत देशी नस्लों की गायों से मिलता है। बाकी 20 प्रतिशत, जिनमें हमारे महिष हैं, जिनको हम भैंसें बोलते हैं और दूसरी संकर और विदेशी नस्ल की गायें हैं। ये 80 प्रतिशत गायें 20 प्रतिशत दूध देती हैं और 20 प्रतिशत जो दूसरा पशुधन है, 80 प्रतिशत दूध देता है। यह अच्छी बात है, लेकिन

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजदूरों के पास, किसानों के पास जो गायें हैं, इनकी ज्यादा चिंता होने का कारण है।

(2एन/एकेजी पर जारी)

AKG-GSP/2N/4.10

श्री राधा मोहन सिंह (क्रमागत) : क्योंकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण परिवार का अंग है। इसका दूसरा महत्व यह है कि जो A2 milk है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह मनुष्य जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमारे एक वक्ता बोल रहे थे। इसका जो गोबर है, मूत्र है, इसका जो वैज्ञानिक महत्व है, हम उसके विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि पंजाब और हरियाणा ने अपने बूते पर A2 milk की अब अलग packaging और processing शुरू की है। भारत सरकार ने भी ओडिशा और कर्नाटक को अलग से राशि दी है और वहाँ इसका अलग से processing plant बना है। A2 milk मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में general व्यवस्था यह है कि हर राज्य के अन्दर जो processing plants हैं, जैसे सुधा है, अमूल है, ये सारे fat के आधार पर दूध लेते हैं। इसलिए जो गाय पालते हैं, उन गौ पालकों को कम कीमत मिलती है और जो दूसरी भैंस वगैरह हैं, उनकी ज्यादा कीमत मिलती है।

आप जो सरकार की बात कर रहे थे, तो मेरे ध्यान में एक बात आई कि आखिर इस सरकार के आने के बाद क्या हुआ और पहले क्या हुआ। जब हम

सरकार में आए, तो हमने देखा कि जो पशुपालन मंत्रालय है, उसमें हम नस्ल सुधार, संवर्धन और संरक्षण का काम करते हैं। इसमें हम जितनी राशि खर्च करते थे, उसमें हम संकर नस्ल और विदेशी नस्ल के दुधारू पशुओं पर ज्यादा खर्च करते थे और 100 में से 95-96-97 प्रतिशत राशि उन पर खर्च करते थे। यह अच्छी बात थी, यह खराब बात नहीं थी, लेकिन हमने तुरंत एक योजना बनाई - 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन'। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन बनाने के बाद विभिन्न राज्यों से 27 परियोजनाएँ आईं और हमने उनके लिए 1,335 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। यह 3 साल पुरानी बात है। इसमें 12 प्रकार के तथ्य दिए गए।

श्री उपसभापति : मंत्री जी, मैं आपको caution देता हूँ कि इस बिल के लिए 2 घंटे का टाइम है। हमें 4.30 बजे से पहले इसे dispose of करना है। इसलिए आप बिल के बारे में बोलिए।

श्री राधा मोहन सिंह : सर, मैं गाय के संरक्षण पर आ रहा हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Remember the time.

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, यहाँ कुछ सवाल उठाए गए हैं, जैसे गाय का संरक्षण। हम 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' लाए। उसमें स्पष्ट है कि जो देसी नस्ल की गायें हैं और जो महिष वंशी हैं, जो देसी नस्ल की हैं, उनके लिए हम 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' लाए और उसका पहला वाक्य है - 'संरक्षण एवं संवर्धन'। इसके तहत विभिन्न राज्यों से 27 परियोजनाएँ आईं। उत्तर प्रदेश के हमारे दोनों

माननीय सदस्य काफी उत्सुकता से इस विषय को रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में, बुंदेलखंड के इलाके में आप शाम में जाइए, तो हजारों गायें ऐसी ही दिखेंगी। मैं एक रात रीवा में था, फिर मैं झाँसी में था। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो उत्पादन होता है, वह एक किलो, आधा किलो होता है या उसने दूध देना बंद कर दिया है। निश्चित रूप से जो किसान है, वह उसके संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उससे उसकी आमदनी नहीं होती। इसीलिए 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के माध्यम से संरक्षण और संवर्धन हो, इस दृष्टि से हमने यह नई योजना शुरू की और राज्यों के माध्यम से हमारी 27 परियोजनाएँ लगभग पूरी हो चुकी हैं।

इसके बाद 'गोकुल ग्राम' की स्थापना हुई, ताकि जो किसान है, वह समझे कि इसके गोबर का कितना महत्व है। अब इसका महत्व क्या है? राष्ट्रीय जैविक केन्द्र में वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर के सूक्ष्म जीवाणुओं को निकाल कर decomposer तैयार किया है। खेत के अन्दर जो केंचुए होते थे, वे पिछले 40-50 वर्ष के अन्दर खेतों में समाप्त हो गए। वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से ही decomposer तैयार किया है, जिसका एक लाख किसान उपयोग कर रहे हैं। देश की 10 बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, जिनमें प्रकाश सिंह बादल जी भी हैं, वे भी उसका अपनी खेती में उपयोग कर रहे हैं। ये सारे तथ्य YouTube पर हैं। इसके संरक्षण के लिए किसानों के अन्दर जागरूकता हो, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई और 'गोकुल ग्राम' का भी निर्माण किया।

(2ओ/आरपीएम पर जारी)

RPM-YSR/2O/4.15

श्री राधा मोहन सिंह (क्रमागत): माननीय उपसभापति महोदय, जिससे इसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए और यदि गाय दूध नहीं देती है, तो उसके गोबर से टाइल्स बनाने, खाद बनाने और उसके मूत्र का भी बहुत बड़ा उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर एक प्राइवेट संस्थान है, उसमें उसके आसपास के पांच किलोमीटर के क्षेत्र के लोग गौ-मूत्र बेचने आते हैं। इस प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों में यह विश्वास पैदा हो कि हमारी सरकार उनके कल्याण के कार्य कर रही है।

महोदय, हमने 12 राज्यों में 18 गोकुल ग्रामों की स्थापना की है। इस प्रकार के ग्राम उत्तर प्रदेश में दो हैं और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में भी हैं। इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की जो बात है, वह यह कि दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां मैंने देखा कि हर देश के अंदर उस देश के पशुओं की देशी नस्लों के सुधार के लिए नेशनल ब्रीडिंग सेंटर हैं, लेकिन हमारे देश में एक भी नेशनल ब्रीडिंग सेंटर नहीं था। हमने इस बारे में पहल की और अब दो नेशनल ब्रीडिंग सेंटर्स स्थापित किए हैं। उनके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने अलग से किया। हमारा एक राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, चिंतलादेवी, जिला नेल्लोर में है। यह शुरू हो गया है। यह 700 एकड़ में है। दूसरा राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, होशंगाबाद-म.प्र. में है। यह तैयार हो रहा है। इस प्रकार हमने दो

राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर खोले हैं। इनमें से एक दक्षिण भारत के लिए है और दूसरा उत्तर भारत के लिए है। मैंने बताया कि राज्यों के अंदर भी हमारी ऐसी 27 परियोजनाएं चल रही हैं। ये बातें मैं इसलिए बात रहा हूं, ताकि गाय की उत्पादकता बढ़े और उसके उपयोग को लोग समझें। इन योजनाओं के माध्यम से गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या किया जा रहा है, वह मैं बता रहा हूं।

महोदय, श्री डी. राजा साहब, वित्त मंत्री जी की ओर इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि गाय के स्वास्थ्य की चिन्ता करें। हम उनकी इस बात से सहमत हैं। अब तक गाय के स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं की गई थी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बाद हमने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय गौमाता उत्पादकता मिशन भी बनाया। मैं बताना चाहता हूं कि अपने देश के अंदर राष्ट्रीय गौमाता उत्पादकता मिशन के तहत, पशु संजीवनी, उन्नत प्रजनन के प्रयोजन हेतु, ई-पशुधन हाट और देशी नस्ल हेतु राष्ट्रीय गौमाता जैविक सेंटर की शुरुआत की गई है। इनकी शुरुआत के परिणाम आप देखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि 8.8 करोड़ दुधारू पशुओं को 12 अंक की विशिष्ट आईडी टैग तथा पशुधन संजीवनी नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना शुरू की है। अभी तक दो करोड़ टैग क्रय करने के साथ-साथ 20 लाख नकुल स्वास्थ्य पत्र की छपाई का काम भी पूरा हो चुका है और इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं।

महोदय, पूरे देश में चिन्हित दुधारू पशुओं में अगले तीन से चार माह में आईडी टैग लगाते हुए, नकुल स्वास्थ्य पत्र भी संबंधित किसानों को पशुओं के स्वास्थ्य की जांच के उपरान्त वितरित किए जाएंगे। यह ठीक है कि यह काम पहले होना चाहिए था। पहले नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है, भले ही विलम्ब हो रहा है। हमारी दो वर्ष की तैयारी का परिणाम अब देश में दिखने जा रहा है।

महोदय, इसी प्रकार से दुग्ध उत्पादक पशुओं के सुगम क्रय-विक्रय हेतु ई-पशुधन हाट की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। आप यदि पता करेंगे और आंकड़े देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि अभी तक सीमन के लिए जो विदेशी और संकर नस्ल के पशु हैं, उनके सीमन डोज़ेज़ ही देश के 90 प्रतिशत लोग खरीदते थे और वही उपलब्ध होते थे। हमने देशी नस्लों के लिए ई-पशुधन हाट पोर्टल बनाया। उसके तहत देश के अंदर सीमन-बैंक भी बने हैं। सीमन-बैंक्स पहले से भी थे, लेकिन अब इन्हें बनाने में और तेजी आई है। उस पोर्टल पर अभी तक देशी नस्लों की 4.50 करोड़ सीमन डोज़ेज़ की बिक्री हुई है। यह रिकॉर्ड है। इसमें बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। देशी नस्लों के जो डोज़ेज़ हैं, उनकी 80 प्रतिशत बिक्री हो रही है और 75 हजार किसानों के पास किस नस्ल की कौन सी गायें हैं, यह जानकारी इस हाट पोर्टल पर उपलब्ध है। लोग उस पोर्टल से जानकारी लेकर उस स्थान पर पहुंच रहे हैं और वहां से क्रय कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि बोवाइन आनुवंशिकी तकनीक से देशी पशुओं की दूध उत्पादकता के चिन्हांकन हेतु

राष्ट्रीय जिनोमिक केन्द्र की स्थापना हेतु आईसीएआर और एनडीआरआई संस्थान, करनाल ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस हेतु 70 हजार पशु उच्च दुग्ध उत्पादकता प्रजाति, जिसमें गीर, साहिवाल एवं अन्य नस्लों की गायों का चिन्हांकन कर डीएनए विश्लेषण किया जा रहा है। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आजादी के काफी लम्बे काल खंड के बाद पिछले तीन या साढ़े तीन वर्षों में चिन्ता की गई है।

(2 पी/पीएसवी पर जारी)

PSV-VKK/2P/4.20

श्री राधा मोहन सिंह (क्रमागत): इसलिए आदरणीय स्वामी जी की जो चिन्ता है, वह जायज़ है। सर, अभी मैं दो-तीन और बातें सदन के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूँ। किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए आज से छ: महीने पहले 10,888 करोड़ रुपये का Dairy Processing and Infrastructure Fund बना। कल के बजट में भी आप देखेंगे, तो पायेंगे कि Fishery and Aquaculture Infrastructure Development Fund plus Animal Husbandry Infrastructure Development Fund के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि, गोवर्धन योजना और हमारे जो पशुपालक हैं, उनके लिए भी KC Card की घोषणा कल की गयी है। तो हमारी सरकार इस दिशा में संरक्षण और संवर्धन के विषय में पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो काम कर रही है, मैं माननीय स्वामी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो भाव है, उसी की पूर्ति में सरकार पूरी

प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है और आगे भी हम इस काम को तेज़ी से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आप सबके माध्यम से माँग करता हूँ कि इसको वापस लिया जाये।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Subramanian Swamy, do you want to reply?

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, you give me five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (NOMINATED): Sir, I will reply to some of the hon. Members' points and then respond to hon. Minister's submissions.

First of all, Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to make it clear that when we say cow, we are talking about a very special breed which in America is called the Indian cow or Brahmin cow. All these kinds of names are given. But, in the Latin word, it is *Bos indicus*. There are two types of cows in the world – one is *Bos indicus* which is only found in India and the other is *Bos taurus* which is found in many parts of the world. Even in India, in the North-East, you find *Bos taurus* but not *Bos indicus*. When I am speaking about preventing the killing of a

cow, I am only talking about *Bos indicus*. Therefore, to bring in all these extraneous issues is not relevant. It is this cow which is specialised in the quality of its milk, its urine and its cow-dung, on which we need to do further research and come to a conclusion. On the question of whether the urine has medicinal properties which is patented, I was challenged to produce the document. I have given the document. There is the licence number, the patent licence number, the registration number and everything, in the document which has been given to the Secretary-General. Anybody can have a look at it. Now that the white-man has said that its urine has medicinal value, I am sure, all of you don't start drinking it from tomorrow. …(Interruptions).. When our *Rishis* said it, at that time, you did not want to believe it. …(Interruptions)… In fact, Mr. Deputy Chairman, Sir, if you look at the Constituent Assembly debate and the first Anti-Cow Slaughter Bill passed in Madhya Pradesh, you will find that Seth Govind Das, a Congressman, Shibban Lal Saxena, a Congressman, and Dr. Rajendra Prasad, etc. were all the men who were in the forefront of saying that cow should be given a special place and that its killing should be banned. I do not know what has happened. Maybe, the Italian

influence has changed the Congress Party today. But the fact is that the original nationalist Congress people were all for it. Also, I want to say that throughout history, there is evidence that the Muslim community never made it an issue that they have a fundamental right to eat cow. In any case, the Supreme Court in two judgments has said that nobody has a fundamental right to eat a cow. It does not form an essential part of any religion. Therefore, that issue is also not there. It is the Englishmen, the white-men, who made it a big fashion and wanted to make it a test whether you are Hindutva man or you are a British stooge. The test was whether you would eat beef before him. That's how it all came in. Now, as far as Mr. Raja is concerned, he got unduly emotional. But the problem is that he has learnt all his history from JNU and his daughter is now one of the prominent agitators there. …(Interruptions)… And his Aryan Dravidian theory is all bogus. I challenge here today in the House. Let Mr. Raja and myself go to a microbiological laboratory and take our blood test to establish our DNA. You will find that it is the same – my DNA and your DNA.

(Contd. by BHS/2Q)

-VKK/BHS-VNK/2Q/4.25

DR. SUBRAMANIAN SWAMY (CONTD.): The DNA of a brahmin and DNA of a Scheduled Caste is the same. The DNA of Indian Hindu and Indian Muslim is also the same. The DNA of all the people from Kanyakumari to Kashmir is the same. Please revise your history. I can ensure that some RSS historians come and give you a tutorial so that your brainwashing is ended.

Secondly, it is not unusual for us to take a symbol like Murugan's peacock and say that nobody can kill peacock. There is a law today banning the killing of a peacock. Nobody is talking about that. Why are they objecting this cow thing? It is because they want to taunt us on our religion. That is the reason. But it has got nothing to do with religion. It has got great economic value and that is why I have brought it. I wanted a law to come and I want the Government to seriously consider putting a cess, a voluntary cess, for the purpose of ensuring that cows are looked after, after they cease to give milk. There should be *gaushalas.* They should be run scientifically. A commission should be set up, which is part of my Bill, for this. The hon. Minister…..(Interruptions)…

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, if a cess is voluntary, why doesn't the Member volunteer to pay the cess? …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. …(Interruptions)… Let him speak. No, please.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Why? I am a Brahmin. I do not pay, I take. …(Interruptions)… Therefore, I am only saying that the whole country is ready to pay. …(Interruptions)… Sir, if you say that we do not have money for *gaushalas,* just ask the people.

Take for example, during the Chinese war in 1962, women took out their gold bangles, chains and necklaces and handed over for the Defence fund of India. I am telling you, on this cow, the country will voluntarily give you all the money you want for *gaushalas.*

So, only thing that remains is a law. Since, he has now said that in consultation with me, he will proceed further in this, I would like to give one more chance to our Government so that I do not have to come back again with another Bill. I think this.….(Interruptions)… I am part of the BJP. I am not going to…..(Interruptions)… I will, therefore, request you to permit me to withdraw the Bill.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. …(Interruptions)… Therefore, has the Member the leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

श्री राजीव शुक्ल : सर, स्वामी जी ने कहा कि कांग्रेस का सेठ गोविन्द दास और शिब्बन लाल सक्सेना.... गौ हत्या पर प्रतिबंध तो कांग्रेस ने लगवाया था, हम भी 1955 में गौ हत्या पर प्रतिबंध के समर्थक थे और हम तो आज भी गौ हत्या पर बैन के समर्थक हैं।...(व्यवधान)... इसमें क्या बात है?....(व्यवधान)... कांग्रेस सरकारें गौ हत्या पर बैन के समर्थक हैं।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, all right. …(Interruptions)… The Bill is withdrawn. …(Interruptions)… Now, Shri Sukhendu Sekhar Ray to move the Bill further to amend the Constitution of India. …(Interruptions)…

SHRI JAIRAM RAMESH: The Member should withdraw. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Member has withdrawn. …(Interruptions)…

SHRI JAIRAM RAMESH: He should withdraw. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, he has withdrawn. …(Interruptions)…

SHRI JAIRAM RAMESH: He should withdraw it himself. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. …(Interruptions)… The Bill is withdrawn. …(Interruptions)… Now, Shri Sukhendu Sekhar Ray.

(Ends)

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2017
(AMENDMENT OF ARTICLE 366)

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (WEST BENGAL): Sir, I am deeply obliged that after six-and-a-half years of my tenure in Rajya Sabha, I have got the opportunity to present my Bill on the Constitutional Amendment, that is, amendment of Article 366 for insertion of Clause 5(A) thereunder. What is this all about?

(THE VICE-CHAIRMAN, DR. SATYANARAYAN JATIYA, in the Chair)

Sir, at the outset, I would like to say that in our Constitution many words and expressions have been properly defined under Article 366 but the word ‘consultation’ has not been defined in our Constitution as

a result of which a lot of controversy and conflict has taken place in this country over the years. Sir, when I am presenting this Bill in this august House, I am appalled to know from a press conference held by senior functionaries of a constitutional institution inviting the attention of the people that rot has been created in the highest body of a particular constitutional institution and the nation cannot avoid addressing this problem.

(Contd. by RL/2R)

-BHS/RL-NKR/4.30/2R

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (CONTD.): And, in a democracy the will of the people is supreme and this will is not only expressed in the Preamble to the Constitution of India but, from time to time, this will of the people is reflected through the discussions and deliberations of the elected representatives of the people. So, now, it is our humble duty on the part of the elected representatives of the people in both Houses of the Parliament to address this serious development which has taken place very recently or maybe since a long time that transparency is absent and some nepotism is going on in a particular constitutional institution and we shall have to address that problem.

Now, Sir, through this Amendment Bill, I propose to insert one Clause (5A) under Article 366 so that the meaning of consultation should only be, "The action or the process of formally consulting or discussing in a merely consultative, advisory and non-binding manner." What prompted me to bring this Constitutional (Amendment) Bill is this and in support of this, I would like to place a few points through you to this House that in our Constitution, in a number of Articles, the very word 'consultation' has been used. It has been used in a number of Articles like Article 124, Article 217, Article 127, Article 222, etc., etc. Now, taking advantage of absence of a proper definition of the word 'consultation', I have already stated on a number of occasions that these provisions of the Constitution have been misutilized, misinterpreted to the benefit of certain quarters which I do not want to name but everybody can understand.

Now, Sir, it is for this reason that the term 'consultation' requires to be defined in the Constitution and this definition should not have any ambiguity. Now, why am I pressing for this Amendment? Sir, first please come to Article 124 of the Constitution. It says, *inter alia*, and I quote, "There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief

Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges, etc." Now, there is a proviso to Article 124. That proviso says, and I quote, "Provided that in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted." Here lies the problem. Previously, there was no problem and it was going on. On the basis of the ordinary dictionary meaning of the word 'consultation', things were moving for a long period but, suddenly, it was derailed. Why? There is a historical background of this. "The Supreme Court in the matter of the Supreme Court Advocates-on-Record Association *vs.* Union of India in the year 1993, and in its Advisory Opinion given in the year 1998 in the Third Judges' case on a reference being made to the Supreme Court by the then President of India under his constitutional powers, had interpreted Clause (2) of Article 124 and Clause (1) of Article 217 of the Constitution with respect to the meaning of 'consultation' as 'concurrence'."

(CONTD. BY DC/2S)

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (CONTD.): From 1993, the scenario suddenly changed and, thereafter also, this Parliament unanimously passed a Constitution (Amendment) Bill and enacted the National Judicial Appointment Commission, which was again set aside by the apex court on the ground of that interpretation that consultation means concurrence. As a student of Political Science and Law, with all respect, I beg to differ with that judgement. What was in the minds of the founding fathers of the Constitution? I would like to refer to a few lines from the Constituent Assembly debate because that is very important. Those who were Members of the Constituent Assembly were not ordinary people. They were much learned than today's people. Sir, on 29th July, 1947, this matter was discussed threadbare, at length, by different leaders in the Constituent Assembly and I would like to refer to a few lines from Volume-IV of the Constituent Assembly debates. I have not brought them. I have got the Parliamentary publications of five volumes and I am having them like many other Members. Here, Clause 18 was introduced in Chapter-IV of the Constituent Assembly debates and Shri Alladi Krishnaswamy Iyer, a lawyer from Madras moved this Clause 18 and it says *inter-alia* and I

quote, “A judge of the Supreme Court shall be appointed by the President after consulting the Chief Justice and such other Judges of the Supreme Court as also such Judges of the High Courts as may be necessary for the purpose.” This was the original Clause or Article which was moved in the Constituent Assembly by Shri Alladi Krishnaswamy Iyer and from there, the discussion started and continued for the entire day and, thereafter, many Members participated in it. I would like to mention one or two lines which other Members said one-by-one on this. First is Mr. Shibban Lal Saksena. Mr. Swamy was referring his name in context of his Bill. Shri S.L. Saksena moved an amendment and said, “In this amendment, I have provided that the Chief Justice of the Supreme Court shall be appointed by the President, but it shall be confirmed by at least two-thirds majority of both the Houses.” A different view was expressed by this gentleman. Now, I come to another Member of the Constituent Assembly, Shri B. Pocker Sahib Bahadur and he said “I move: That for clause (2) and the first proviso of clause (2) of Article 103, the following be substituted:- Every judge of the Supreme Court other than the Chief Justice of India shall be appointed by the President by warrant under

his hand and seal after consultation with the concurrence of the Chief Justice of India." He advocated for concurrence of the Chief Justice of India, not only consultation. So, again, there is a different view. But ultimately, when divergent views were expressed by various Members in the Constituent Assembly—I don't want to proceed further—I would like to quote one or two lines of some of the Members and I quote, "If a Judge owes his appointment to a political party, certainly, in the course of his career as a Judge, also as an ordinary human being, he will certainly be bound to have some consideration for the political views of the authority that has appointed him. That the Judges should be above all these political considerations cannot be denied. Therefore, I submit that one of the chief conditions mentioned in the procedure laid down, that is the concurrence of the Chief Justice of India in the appointment of the Judges of the Supreme Court, must be fulfilled." So, he went on saying why this concurrence is required. Mere consultation will not do; concurrence is required and he said that it should be accepted by the House. Then another Member, Mr. K.T. Shah said and I quote, "This is an amendment seeking to make the appointment of Judges free from any particular influence."

(Contd. by KR/2T)

KR/2t/4.40

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (CONTD.): My amendment is that the President, if he makes the appointment, naturally, he will do so on the advice of the Prime Minister. In my opinion, Sir, if I may say so with all respect this Constitution concentrates so much power and influence in the hands of the Prime Minister in regard to the appointment of Judges, Ambassadors, Governors, etc., etc., etc., again a different view.

Mr. Das Bhargava, another Member of the Constituent Assembly, had supported the amendment saying, "Confirmation of the appointment of the Chief Justice of the Supreme Court must be made by a two-thirds majority of the total number of Members of Parliament assembled in a joint session of both Houses of Parliament." So, this is another view that this should be approved by the two-thirds majority of the Members assembled in a Joint Session of Parliament. So, the discussion was going on at length, and what happened ultimately? Out of those discussions somebody said, "This is the formula; no, no, there is another formula, there is third formula and there is fourth formula."

Ultimately, Dr. B.R. Ambedkar, the main architect of the Constitution and the Chairman of the Draft Committee, said, “It should be taken as a concluding part of the debate.” I quote, “Now, Sir, with regard to the numerous amendments that have been moved, to this article, there are really three issues that have been raised.” He has summarized three issues on the question of consultation or concurrence or two-thirds majority for Parliament to pass, etc., etc. He has framed three issues. The first is how the Judges of the Supreme Court should be appointed. This is the first issue. “Now grouping the different amendments that are related to this particular matter, I find three different proposals.” I mean, Dr. B.R. Ambedkar, not me. “The first proposal is that the Judges of the Supreme Court should be appointed with the concurrence of the Chief Justice.” That was one view, which I have already stated. “The other view is that the appointments made by the President should be subject to the confirmation of two-thirds vote by the Parliament. The third suggestion is that they should be appointed in consultation with the Council of States.” Somebody suggested that it should be in consultation with this House, the Council of States. So, there were various suggestions but Dr. B.R. Ambedkar referred to

these three issues. Then, Dr. Ambedkar continued, “There can be no difference of opinion in the House that our judiciary must both be independent of the Executive” – and in the Constitution there is an article 48, which says that the Judiciary should be separated from the Executive, we have already adopted -- “and must also be competent in itself, and the question is how these two objects could be secured.” Judiciary is not only to be independent but it should also be competent in itself. That is the moot question. How the judiciary can achieve to be competent in itself? Is it through nepotism, high-handedness? It can’t be. Therefore, what has Dr. Ambedkar suggested? “There are two ways in which this matter is governed in other countries. In Great Britain the appointments are made by the Crown, without any kind of limitation whatsoever, which means by the Executive of the day. There is the opposite system in the United States where, for instance, appointment of officers of the Supreme Court as well as other officers of the state shall be made only with the concurrence of the Senate in the United States.”

(Continued by 1U/KS)

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (contd.): So, Dr. Ambedkar had referred to Great Britain and the United States as to how Judges and other officials of the Supreme Court were appointed. "It seems to me", Dr. Ambedkar says, "in the circumstances in which we live today, where the sense of responsibility has not grown to the same extent to which we find it in the United States, it would be dangerous to leave the appointments to be made by the President without any kind of reservation or limitation, that is to say, merely on the advice of the Executive of the day." He had also advocated that there should not be given any unflinching power to the President for appointment of Supreme Court Judges; there must be some restrictions because we have not yet emerged as a nation to the height of the United States. Indirectly, this is what he wanted to say, if I have correctly understood the purport and the meaning of what he had said.

Now, Sir, again, he says, "Similarly, it seems to me that making every appointment that the Executive wishes to make, subject to the concurrence of the Legislature, will also not be a very suitable proposition", which meant, neither appointment by Judges was desirable, nor this is desirable that for every appointment the Executive

has to seek approval of the Parliament. That is also not desirable. Then, what was desirable and what should be which is in-between and which is a balancing act or a compromise. Then, what he prescribed and what he advocated was that, "Apart from its being cumbrous, it also involves the possibility of the appointment being influenced by political pressure and political considerations." The draft article, that is, Article 80, which I had read at the outset, says, "In consultation with the Chief Justice, the Judges would be appointed by the President, under his hand and seal." He says,"The draft article, therefore, steers a middle course. It does not make the President the supreme and absolute authority in the matter of making **appointments**. It does not **also** import the influence of the Legislature. The provision in the article is that there should be consultation of persons who are *ex hypothesi*, well-qualified to give proper advice in matters of this sort, and my judgement is that this sort of provision may be regarded as sufficient for the moment."

He continued, "With regard to the question of the concurrence of the Chief Justice" – he dealt with this part very widely – "it seems to me that those who advocate that proposition seem to rely implicitly

both on the impartiality of the Chief Justice and the soundness of his judgement. I personally feel that there is no doubt that the Chief Justice is a very eminent person but, after all, the Chief Justice is a man with all the failings, all the sentiments and all the prejudices which we as common people have. So, he is not a great human being or a greater human being; the Chief Justice is also a human being like all other human beings, which Dr. Ambedkar tried to propagate and convince the Members of the Constituent Assembly very successfully. He continued to say, "I think, to allow the Chief Justice practically a veto upon the appointment of Judges is really to transfer the authority to the Chief Justice which we are not prepared to vest in the President or the Government of the day. So, this Constituent Assembly wants to give absolute authority neither to the President nor to the Legislature nor even to the Chief Justice. Therefore, there should be a balance, a consulting process and democracy requires this process; democracy requires consultation; democracy requires debate and, thereafter, approval.

(CONTD. BY RSS/2W)

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (CONTD.): Therefore, Dr. Ambedkar ruled out the phasing out of concurrence in the process of consultation for appointment of judges, either in the Supreme Court or in the High Courts. Unfortunately, after following this procedure over the decades, suddenly, in 1993, all of us know what happened and how it happened, and India is the only country in the world where judges appoint judges. Nowhere in the world does it happen. In Switzerland, the Federal Assembly appoints the judges of the Federal Court. This Parliament never sought for that power nor the Constituent Assembly ever wanted that that power should be given either to the Legislature or to the President of India. Therefore, Sir, unfortunately this has happened, and what was the recommendation of the National Commission to Review the Working of the Indian Constitution? This Constitution was reviewed by the National Commission to Review the Working of the Indian Constitution in the year 2002. The report was submitted in the year 2002. I quote two, three lines of this report with your kind permission. It says: "It would be worthwhile to have a participatory role with the participation of both the Executive and the Judiciary in making recommendations. The Commission proposes the composition of the

collegium which gives due importance to, and provides for the effective participation of both the Executive and the Judicial wings of the State, as an integrated scheme or machinery for the appointment of judges." What would be the noble idea better than that? The Commission accordingly recommended the establishment of the National Judicial Commission, and we have seen the fate of the National Judicial Commission...(Interruptions)... I need ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Some other speakers may speak.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : आप अच्छा बोल रहे हैं। आप कंटिन्यू करिए, दस मिनट तक यही करना है।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Thank you, Sir. Kindly permit me because it is a very important subject.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आप दो मिनट पहले कन्क्लूड कर लेंगे, तो दूसरा स्पीकर बोल लेगा। ...(व्यवधान)...

श्री सुखेन्दु शेखर राय : सर, यह जजमेंट है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है, ठीक है।

श्री सुखेन्दु शेखर राय : मैं बाकी जजमेंट्स को दूसरे दिन पेश करूंगा, लेकिन जो salient points हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कृपया आप आज मुझे कन्क्लूड करने के लिए मत बोलिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : इसके लिए दो घंटे का समय है, अगर दूसरा स्पीकर दो मिनट भी बोल लेगा, तो वह कंटिन्यू करेगा और फिर आपको रिप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है।

श्री सुखेन्दु शेखर राय : ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। Sir, late Justice Verma was the main architect of the Second Judges Case, and after his retirement, we, some of the Members of this House, were in the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, and had the opportunity to meet him as a witness. He came to this Committee to give his evidence on the Lokpal Bill. There he said, and in other places also he said, it is on record, and I quote two, three lines of what he said. Late Justice Verma said: "My 1993 judgment has been both misunderstood and misused, the main architect, who gave birth to this typical collegium formula. Therefore, some kind of rethink is required on my judgment, and the appointment process of High Court and Supreme Court judges is basically a joint or a participatory exercise between the Executive

and the Judiciary, both taking part in it." Now, simply some people may claim that it is still there. This is the participation of both Executive and the Judiciary. But, no; whatever will come from the Judiciary, that will have a binding effect on the Executive and the Head of the State, the President of India.

(contd. by 2x/KLS)

KLS/2X-4.55

SHRI SUKHKENDU SEKHAR RAY (CONTD): He is bound by the recommendations of the judiciary; he cannot have any other option. Sir, there is limited time, I would like to say many things because so many articles are there, how consultation mode has been used and in what context and how the court interpreted this particular word in a particular case, if the other authorities claim that when my consultation is required or something, that will have the binding effect on the President of India, then you are going to denigrate the position held by the President under the Constitution. This is why, Sir, I want that this debate should be continued, this matter should be discussed again and again and this issue must be kept alive and the Government must ultimately intervene to address the problem because already it has

come on the surface. Press conference is being held; something is being said which is not really very healthy for our democracy. Today I have referred to views of certain Members of our Constituent Assembly. Next time when I will get the opportunity either for reply or for continuation of my speech, I will place before you and, through you, before the House how the Constitution has been rewritten, not by the Parliament but outside the Parliament. This I would like to establish in my next submission, through you, before this august House. Thank you, Sir.

The question was proposed.

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA (KARNATAKA): Mr. Vice-Chairman, Sir, actually you were supposed to intervene in this debate, but since you are occupying the Chair now, it has suddenly fallen on me. …(Interruptions)… There is a lot of erudition. This is one Bill in which I find that the Statement of Objects and Reasons contains a lot of erudition and it is quite a pleasant reading of the whole thing. But, the amendments suggested, I have some reservations in that. I feel the Objects and Reasons are almost like a sledgehammer to crack a nut. Certainly the provocation for this entire Bill is somewhat

controversial pronouncements that consultation is concurrence, which is totally wrong. But does it mean that we should have a Constitutional Amendment in which it may solve the problem in this particular respect, but it can create more problems in various other provisions of the Constitution? In legislative drafting, it often appears necessary to have precision in language. But, at the same, many times we find that a little bit vagueness is more useful than complete precision. Now let me take an example. We have recognized many institutions as Institutions of National Importance or Centres of Excellence and it is never defined in any particular legislation what is the Centre of Excellence or what is the Institution of National Importance. Now, if you fetter the discretion by a precise definition, then it will create problems in other areas. (Contd. By 2Y/SSS)

ASC/SSS/5.00/2Y

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA (CONTD.): Even coming to the Constitution itself, there is an article…

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : रामाकृष्णा जी, इसको अगले समय तक के लिए जारी रखिए, क्योंकि अभी सदन का समय पूरा हो रहा है। आप इसको आगे जारी रख सकते हैं।

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA: Shall I finish now?

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) : आप इसको अगले समय के लिए जारी रख सकते हैं। आपने शुरू कर दिया है, इसलिए यह जारी रहेगा।

Now, we will take up Special Mentions. Shri K. C. Ramamurthy. Not present. Shri Vivek Gupta. Not present. Shri P. L. Punia.

(Ends)

SPECIAL MENTIONS

DEMAND FOR REMOVING IRREGULARITIES EXISTING IN PROVISIONS OF RESERVATION FOR SCs/STs AND OBCs IN EMPLOYMENT

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश) : महोदय, देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 16.6, जनजाति 8.6, ओबीसी 52 और सामान्य जातियां 23 प्रतिशत हैं। मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति को 15 परसेंट, जनजाति को 7.5 परसेंट और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देती है। इस तरह देश की 77 प्रतिशत पिछड़ी जातियों को केवल 49.5 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है तथा शेष 50.5 प्रतिशत आरक्षण 23 प्रतिशत सवर्ण जातियों को दिया जा रहा है। फिर भी आरक्षित वर्ग का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है।

भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 22.05.1989 तथा 02.07.1997 के प्रावधानों के अुनसार आरक्षित उम्मीदवार जो मैरिट लाकर

सामान्य उम्मीदवारों के लिए तय किए गए स्टेंडर्ड को पूरा करते हैं, उन्हें आरक्षित पदों में नहीं भरा जाएगा।

लेकिन 01.07.1989 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार यदि आरक्षित उम्मीदवार आवेदन शुल्क, आयु, सीमा, लिखित परीक्षा की संख्या में छूट आदि रियायतें लेता है, तो मैरिट में आने के आद भी उसे आरक्षित वर्ग में ही चयनित माना जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 06 अप्रैल, 2017 को दीपा ई.वी. (अपीलेंट) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य (रिस्पॉंडेंट) के मामले में भी इसी प्रकार का फैसला सुनाया है।

आरक्षित वर्ग को रियायतें, एक समान खेल मैदान प्रदान करने के लिए दी जाती हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रतिस्पर्द्धा के लिए पात्र बनाया जा सके।

अत: आपके माध्यम से निवेदन है कि जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाए और आरक्षण व्यवस्था में व्याप्त अस्पष्टता को दूर करते हुए मैरिट को चयन का आधार बनाया जाए।

(समाप्त)

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (TELANGANA): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Shri P. L. Punia.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shri Sanjay Raut. Not present. Shri Lal Sinh Vadodia. Not present.

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 5 फरवरी, 2018 को 11.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

…

The House then adjourned at three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 5th February, 2018.